



NATIONAL ELECTION WATCH



*Analysis of Bye Election for 31 Assembly & 1 Lok Sabha Constituency on 7<sup>th</sup> November, 2009*

**29 candidates with self declared pending criminal charges contesting bye election on November 07, 2009 in 7 states**

**Out of these 29 candidates, 8 candidates have declared rape, murder and attempt to murder charges against them (maximum from Uttar Pradesh)**

**Candidates with Murder/kidnapping related charges given tickets by BSP, SP, BJP, AITC, CPI(M)**

**नई दिल्ली, दिनांक 03 नवम्बर 2009** : एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एवं नेशनल

इलेक्सन वॉच एक राष्ट्रीय अभियान है

जिसमें 1200 से अधिक गैर सरकारिक संगठन और कई दूसरे नागरिक संगठन साथ मिलकर चुनाव सुधार, प्रजातांत्रिक सुधार एवं सुसासन के लिये कार्य करते हैं.

सात राज्यों ( हिमांचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश , छत्तीसगढ़ , राजस्थान , केरला , असम और वेस्ट बंगाल) में सात नवम्बर को होने वाले विधान सभा एवं

लोक सभा उप चुनाव में 313 उम्मीदवार खड़े हैं, जिनमें से 157 उम्मीदवारों के हलाफनामो का नेशनल इलेक्शन वॉच ने विश्लेषण किया है.

### **विश्लेषण के मुख्य बिंदु**

(१) सात राज्यों में कुल 157 उम्मीदवारों का विश्लेषण किया गया

(२) इनमें 29 उम्मीदवारों पर अपराधिक मामले लंबित

(३) इन 29 उम्मीदवारों में से 12 उम्मीदवारों पर गंभीर अपराधिक मामले लंबित

(४) अपराधिक मामले वाले उम्मीदवारों में सबसे अधिक ( 67 में से 19 ,लगभग 28.35 %) उम्मीदवार उत्तर प्रदेश है

और दूसरा स्थान केरल का है जिसमें 11 में से 5 (45.45 % ) पर अपराधिक मामले लंबित है

(५) राजनैतिक दलों में INC से 25 में से 7 (28%) उम्मीदवारों पर अपराधिक मामले लंबित है जबकि SP से 11 में से 5 (45.45%) ,

BJP से 27 में से 5 (18.51%), BSP में 12 में से 4 (30%) के ऊपर अपराधिक मामले लंबित है

(६) गंभीर मामले हत्या , हत्या करने का प्रयास और चोरी इत्यादी वाले उम्मीदवारों में BSP - 4 , SP - 2 ,

AITC - 1 , BJP - 1 , CPI (M) - 1, All India Forward Block -1, IND - 2

- (७) इनमें 8 उम्मीदवारों के ऊपर बलात्कार, हत्या और हत्या करने के प्रयास के मामले लंबित हैं इनमें उत्तर प्रदेश से 6, केरल से 1 तथा पश्चिम बंगाल से 1 हैं
- (८) कुल 157 उम्मीदवारों में से 22 उम्मीदवार करोड़ पति हैं जिनकी सम्पति एक करोड़ से अधिक है इनमें सबसे अधिक SP से 6 (12 में से 6, 50%) , इसके बाद INC से 5 (25 में से 5 , 20%) , BSP से 4 (12 में से 4 , 33.33%) , BJP में 4 (27 में से 4 , 14.81%) , AITC में 1 (7 में से 1 , 14.28%) हैं
- (९) अधिक सम्पति वाले उम्मीदवारों में से पहले स्थान पर INC के राजबब्बर (11.70 करोड़ रुपये ) फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, दुसरे स्थान पर BJP के राजेश पाण्डेय (6.77 करोड़ रुपये ) पडरौना उत्तर प्रदेश , तीसरे स्थान पर SP की डिम्पल यादव (5.27 करोड़ रुपीये) फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश उम्मीदवार हैं
- (१०) सबसे अधिक 16 करोड़पति (67में से 16 , 23.88% ) उम्मीदवार उत्तरप्रदेश से है उसके बाद छत्तीसगढ़ से 3 (15 में से 3, 20%) हैं
- (११) सबसे अधिक अपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार झाँसी विधान सभा (उत्तर प्रदेश) और अलाप्पुज्हा विधान सभा( केरल ) से क्रमशः 3-3 हैं

## Contact

Anil Bairwal, National Coordinator National Election Watch, and Association for Democratic Reforms 011 6590 1524, +91 9999310100 <a href="mailto:adr@adrindia.org">adr@adrindia.org</a> , <a href="mailto:anil@adrindia.org">anil@adrindia.org</a>	Prof Trilochan Sastry Dean, IIM Bangalore Founder Member, National Election Watch, Association for Democratic Reforms +919448353285, <a href="mailto:trilochans@IIMB.ERNET.IN">trilochans@IIMB.ERNET.IN</a>	Prof Jagdeep Chhokar Former Director IIM Ahmedabad, Founder Member National Election Watch, Association for Democratic Reforms +919999620944 <a href="mailto:jchhokar@gmail.com">jchhokar@gmail.com</a>
--	--	---

## About NEW

The *National Election Watch (NEW)* is a nationwide campaign comprising of more than 1200 NGO and other citizen led organizations working on electoral reforms, improving democracy and governance in India. The National Election Watch is active in almost all states of India and has done election watch for all states and Lok Sabha elections since ADR, along with couple other organizations, won the PIL in Supreme Court in 2002 to making disclosure of educational, financial and criminal background of electoral candidates mandatory.

## About ADR

Association for Democratic Reforms (ADR) is a Non-Political, Non-Partisan and a Non-Governmental Organization whose PIL filed in Dec 1999 culminated in a Supreme Court order on Mar 13, 2003 requiring disclosure of criminal, financial and educational background of all contesting candidates. Since then ADR has done Election Watches in almost all State Assembly and Lok Sabha elections. It continues to works towards strengthening democracy and governance in India by focusing on fair and transparent electoral and political processes.

You can learn more about ADR at: <http://www.adrindia.org>